

भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्राप्ति: 17.11.2023

स्वीकृत: 24.12.2023

डॉ० सविता तोमर

एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
संजय गाँधी (पी०जी०) कॉलेज, सररपुर खुर्द, मेरठ
ईमेल: drsavita1011@gmail.com

79

सारांश

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्वभर में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। इसलिए भारत सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वह सभी के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करवाने तथा गाँवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने हेतु "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" को शुरू किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई जोकि एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के अनेक अवसरों को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करना है। भारत की कुल आबादी का 65 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है, अतः इस आबादी के लिए रोजगार के साधनों के विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था का विकास तथा समृद्धि सम्भव है।

परिचय

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) के तेजी से बढ़ने के बावजूद भी देश की एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रही है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी सरकार के लिए ग्रामीण निर्धनता सभी स्तरों पर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। गरीबी उन्मूलन तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 जून 2011 को यह योजना शुरू की गई, इसे केन्द्र सरकार की पूर्व योजना "स्वर्ण जयन्ती ग्राम" स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) को पुनर्गठित कर 1 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू किया गया। 29 मार्च 2016 को इसका नाम बदलकर "दीनदयाल अंत्योदय योजना (Day-NRIM) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया।

भारत की कुल आबादी का 65 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है और इन क्षेत्रों की महिलाओं को भारत को पाँच (5) ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने हेतु सभी संभव अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा बनाया जाता है ताकि जी०डी०पी० में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तथा देश की महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

योजनाओं की विशेषतायें

- निर्धन ग्रामीण लोगों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।
- पात्रता रखने वाले ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना।
- सभी सीमांत ग्रामीण और कमजोर परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के अन्तर्गत लाना।
- यह योजना भारत के सभी राज्यों में 101 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने के विचार के साथ चलाया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का विकास कर ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना।
- औपचारिक ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना।
- आजीविका के विविधिकरण तथा सुदृढीकरण के लिए समर्थन करना।

कार्य पद्धति

- इस योजना के तहत स्वयं सहायता की भावना का विकास कर सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य किया जाता है।
- इसके तहत ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SHG) में संगठित किया जाता है।
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है।
- स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण क्षमता निर्माण में सहायता की जाती है।
- स्वयं के संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना।

अध्ययन का उद्देश्य

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भौतिक (वास्तविक) प्रगति का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय प्रगति का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि— रैण्डमैंन और मोशी के अनुसार— नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। प्रस्तुत शोध में वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन भारत सरकार की केन्द्रीय योजना “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

समकों का प्रकार व स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीय समकों पर आधारित है। अध्ययन के द्वितीय समकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय की एन0आर0एल0एम0 की रिपोर्ट, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन एवं शोध अध्ययनों आदि का समावेशन किया गया है।

समकों का विश्लेषण

देश के आर्थिक विकास तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए ग्रामीण जनसंख्या का आर्थिक रूप से सशक्त होना अनिवार्य है। इसका अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारत में रोजगार

योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। जिसका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे:-

अ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की भौतिक (वास्तविक) प्रगति का अध्ययन।

इस शीर्षक के अन्तर्गत उन परिवारों की संख्या को जिन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, स्वयं सहायता समूहों की संख्या, तथा प्रगतिशील ग्राम संगठनों की संख्या का विश्लेषण कर एन0आर0एल0एम0 की वास्तविक प्रगति का अध्ययन किया गया है।

i) Number of Households Mobilized Into SHG (स्वयं सहायता समूह में संगठित परिवारों की संख्या)

Year	Number of Households Mobilized into SHG
2018-19	55858322
2019-20	64597626
2020-21	71501133
2021-22	78236805

Source: ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका में विभिन्न वर्षों में स्वयं सहायता समूह में संगठित परिवारों की संख्या को दर्शाया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में ऐसे परिवार जो स्वयं सहायता संगठनों में जुड़े थे, उनकी संख्या 55858322 थी जो वर्ष 2021-22 तक क्रमशः बढ़ती रही तथा 78236805 हो गयी।

अतः वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि में स्वयं सहायता समूह में संगठित परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

ii) Number of SHGS (स्वयं सहायता समूह) Promoted (स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया)

इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की संख्या का विश्लेषण कर यह अध्ययन किया गया है कि कितने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है इसका विश्लेषण निम्न तालिका द्वारा किया गया है-

Number of SHGS Promoted

Year	No. SHGS Promoted
2018.19	5022609
2019.20	5839721
2020.21	6491976
2021.22	7153922

Source – ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका में विभिन्न वर्षों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 2018-19 में 5011609 स्वयं सहायता समूहों को प्रमोट किया गया जिनकी

संख्या 2021–22 में बढ़कर 7153922 हो गयी। अतः वर्ष 2018–23 तक स्वयं सहायता समूह की संख्या में वृद्धि हुई है।

iii) Number of Village Organisations Promoted (ग्राम संगठनों की संख्या को प्रमोट किया गया)

इसके अन्तर्गत प्रमोट हुए ग्राम संगठनों की संख्या को दर्शाया गया है, जिसका विश्लेषण निम्न तालिका के माध्यम से किया गया है।

Number of Village Organization Promoted

Year	Number of V.O.P.
2018–19	267676
2019–20	327357
2020–21	371255
2021–22	413859

Source – ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका में वर्ष 2018–19 में प्रमोट हुए ग्राम संगठनों की संख्या 267676 दर्ज की गई है, जिनमें वर्ष 2021–22 तक क्रमशः वृद्धि दर्ज की गई तथा वर्ष 2021–22 में इनकी संख्या बढ़कर 413859 हो गई अतः वर्ष 2018 से 2023 तक ग्राम संगठनों को प्रोत्साहित किया गया है।

ब) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय प्रगति का अध्ययन–

इस शीर्षक के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को वितरित की गई चक्रीय निधि की राशि के आँकड़ों का विश्लेषण कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय प्रगति का अध्ययन किया गया है।

Amount of Revolving Fund disbursed of SHG (in lakh)

(स्वयं सहायता समूहों को वितरित की गई चक्रीय राशि की निधि (लाख में))

Year	Amount of Revolving Fund disbursed to SHG (In Lakh)
2018–19	23566282698
2019–20	30331914548
2020–21	37877328048
2021–22	46054982048

Source – ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक की अवधि में स्वयं सहायता समूहों को वितरित की गई चक्रीय राशि की निधि में क्रमशः वृद्धि दर्ज की गई है।

निष्कर्ष

इन आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि भारत सरकार की “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” नामक योजना ने वित्तीय तथा भौतिक प्रगति को सुनिश्चित किया है।

- अध्ययन की अवधि (वर्ष 2018–22) में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों में जुड़ने वाले परिवारों की संख्या

में वर्षद्वि दर्ज की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि एन0आर0एल0एम0 की वास्तविक (भौतिक) प्रगति सुनिश्चित हुई है।

- अध्ययन की अवधि (वर्ष 2018–22) में स्वयं सहायता समूहों को वितरित की गई निधि में भी वर्षद्वि दर्शित है जिससे स्पष्ट होता है कि एन0आर0एल0एम0 की वित्तीय प्रगति भी हुई।
- अतः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है, तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिला है, जिसके माध्यम से अनेक परिवारों की महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

सुझाव

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं—

- स्वयं सहायता समूहों की प्रत्येक महिला सदस्य को प्रशिक्षण दिया जाए।
- ग्रामीण इलाकों के युवाओं में कौशल को विकसित करने हेतु उचित योजनायें बनायीं जायें। ताकि युवा स्वरोजगार के लिए प्रेषित हो सकें।
- स्वयं सहायता समूहों में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त हो जायेगीं।
- स्वयं सहायता समूह में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयास आवश्यक हैं। सरकार जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु तथा स्वयं सहायता की प्रगति के लिए उचित वित्तीय प्रबन्धन हो।
- स्थानीय सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” से संबंधित सूचनाओं, जानकारियों तथा विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत करवाये।

सन्दर्भ

1. Gupta, Des., Monidipa., Roy, Nirupom. (2017). “National Rural Livelihood Mission (NRLM) and sustainable Livelihood Development through Poverty Alleviation”.
2. Surendran, A. (2013). “National Rural Livelihoods Mission Progress Towards Rural Upliftment in India”.
3. Shah, Alom. (2018). “Impact of National Rural Livelihood Mission on Empowering Women”.
4. Patil, Hanumanth. “A Study on National Rural Livelihood Mission – A Government Initiative for women empowerment”.
5. Sinha, Kamini., Agrawal, Sumeet. (2022). “National Rural Livelihood Mission & Rural Women Empowerment”.
6. Mahak., Kumar, Bijender. “Progress towards Rural upliftment in India by NRLM.